मुद्रा-स्फीति को रोकने के उपाय
(MEASURES TO CHECK INFLATION)

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मुद्रा-स्फीति को रोकने वाले उपायों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है जैसाकि निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है :

मुद्रा-स्फीति को रोकने के उपाय

मौद्रिक उपाय

(i) मुद्रा की मात्रा पर नियन्त्रण
(ii) करेन्सी का विमुद्रीकरण
(iii) साख नियन्त्रण :

राजकोषीय उपाय

(i) कर में वृद्धि
(ii) सार्वजनिक ऋण में वृद्धि
(iii) सार्वजनिक व्यय में कमी

अन्य उपाय

(i) उत्पादन में वृद्धि
(ii) लाभ वितरण पर प्रतिबन्ध
(iii) सट्टेबाजी पर प्रतिबन्ध

Scanned with CamScanner

(अ) बैंक दर में वृद्धि
(ब) न्यूनतम नगद कोष में वृद्धि
(स) सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना
(द) साख राशनिंग
(य) मार्जिन में वृद्धि

(iv) बचतों को प्रोत्साहन
(v) विनियोग पर नियन्त्रण
(vi) मुद्रा का अधिमूल्यन

(iv) मूल्य नियन्त्रण व राशनिंग
(v) आयात प्रोत्साहन
(vi) मजदूरी नीति

(1) **मौद्रिक उपाय** (Monetary Measures)—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के साथ-साथ कई आधुनिक अर्थशास्त्री, जैसे—**मिल्टन फ्रीडमैन** (Milton Friedman), **डॉन पैटिन्कन** (Don Patinkin) का भी मत है कि मुद्रा-स्फीति को मुद्रा की पूर्ति में नियन्त्रण करके रोका जा सकता है। मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए केन्द्रीय बैंक द्वारा जो उपाय किये जा सकते हैं, संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

(i) **मुद्रा की मात्रा पर नियन्त्रण** (Control over Money)—मुद्रा की मात्रा को नियन्त्रित कर मुद्रा-स्फीति को रोका जा सकता है। इस हेतु सरकार को केन्द्रीय बैंक द्वारा की जाने वाली मुद्रा निर्गमन पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए।

(ii) **पुरानी करेन्सी का विमुद्रीकरण** (Demonetization of Old Currency)—जब मुद्रा-स्फीति खतरनाक अवस्था में पहुँच जाती है तो सरकार पुरानी मुद्रा समाप्त करके नई मुद्रा जारी कर सकती है। सरकार कुछ निश्चित समय में पुरानी मुद्रा की कुछ निश्चित मात्रा को नई मुद्रा में बदलने की अनुमति दे सकती है।

(iii) **साख नियन्त्रण** (Credit Control)—मुद्रा-स्फीति को नियमित करने के लिए केन्द्रीय बैंक को साख नियन्त्रण या साख का संकुचन करना चाहिए। इसके लिए **परिमाणात्मक** (Quantitative) तथा **गुणात्मक** (Qualitative) दोनों प्रकार के उपाय अपनाये जाने चाहिए। केन्द्रीय बैंक को निम्न प्रकार के उपाय अपनाये चाहिए :

(अ) बैंक दर में वृद्धि, (ब) न्यूनतम नकद कोष में वृद्धि, (स) सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचना, (द) साख की राशनिंग, (य) मार्जिन या सीमान्त आवश्यकता में वृद्धि इत्यादि। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को इस प्रकार के निर्देश जारी कर सकता है जिससे वे साख निर्माण को सीमित कर दें।

मौद्रिक उपाय की सीमाएँ (Limitations of Monetary Measures)—इन मौद्रिक उपायों की निम्न सीमाएँ होती हैं :

(अ) अकेले मौद्रिक उपचार ही मुद्रा-प्रसार पर रोक लगाने हेतु सफल प्रमाणित नहीं हुए हैं। उदाहरण के लिए, सन् 1929-33 में अमेरिका में कठोर साख नीति का पालन करने पर भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती रहीं; (ब) वास्तविक विनियोगकर्त्ताओं पर अंकुश रखने में सरकार असमर्थ रहती है तथा (स) मौद्रिक नीति प्रायः इतनी कोमलता से लागू की जाती है कि इसकी व्यावहारिक उपयोगिता नहीं के बराबर होती है।

(2) **राजकोषीय उपाय** (Fiscal Measures)—इस श्रेणी में सरकार के वे सभी वित्त सम्बन्धी उपाय आते हैं जो चलन में मुद्रा की मात्रा कम करने में सहायक होते हैं; जैसे—कर, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण। इनसे सम्बन्धित नीतियों की संक्षिप्त व्याख्या नीचे दी जा रही है :

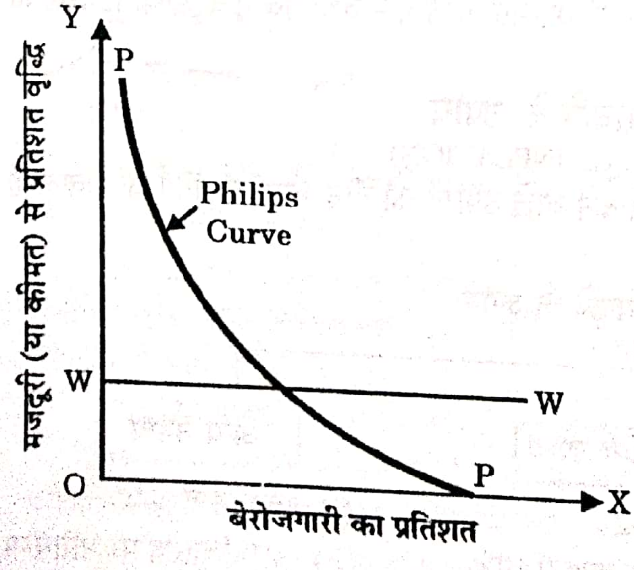

चित्र 5.3

(i) **कर में वृद्धि** (Increase in Taxes)—मुद्रा-स्फीति पर नियन्त्रण लगाने के लिए सरकार को जनता की अतिरिक्त क्रय-शक्ति को कम करने हेतु कर में वृद्धि करने की दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए। ऐसी स्थिति में फालतू क्रय-शक्ति वसूल कर ली जाती है।

(ii) **सार्वजनिक ऋण में वृद्धि** (Increase in Public Debts)—मुद्रा-स्फीति को कम करने के लिए सरकार को अधिकाधिक मात्रा में लोगों से ऋण वसूल करना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त किये गये धन को उत्पादन

Scanned with CamScanner

कार्यों में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। परिणामस्वरूप एक ओर तो जनता में क्रय-शक्ति की कमी हो जाती है और दूसरे, उत्पादन की मात्रा भी बढ़ने लगती है।

(iii) **सार्वजनिक व्यय में कमी** (Reduction in Public Expenditure)—स्फीतिकाल में सरकार को चाहिए कि वह यथासम्भव अपने व्यय में कटौती करे, विशेषकर अनुत्पादक व्यय को कम करना अत्यन्त आवश्यक होता है।

(iv) **बचतों को प्रोत्साहन** (Encouragement to Savings)—सरकार की अपनी वित्त सम्बन्धी नीति के द्वारा उपभोग को हतोत्साहित और बचतों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह उपभोग की वस्तुओं पर कर लगाकर तथा बचत सम्बन्धी उपायों का प्रचार कर मुद्रा-स्फीति पर नियन्त्रण करे।

(v) **विनियोग पर नियन्त्रण** (Control on Investment)—मुद्रा-स्फीति के परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इससे व्यापारी एवं उद्योगपति लाभ कमाकर अपनी पूँजी व्यवसायों के विस्तार में लगाते हैं जिससे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः सरकार को चाहिए कि स्फीति-काल में विनियोग पर नियन्त्रण रखे।

(vi) **मुद्रा का अधिमूल्यन** (Devaluation of Money)—इससे विदेशों को आयात सस्ते और निर्यात महँगे हो जाते हैं। इससे दोहरा लाभ प्राप्त होता है। आयात बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है और निर्यात कम होने से उपलब्ध पूर्ति में वृद्धि हो जाती है जो बढ़ते मूल्यों पर नियन्त्रण में उपयोगी है।

(3) **अन्य उपाय** (Other Measures)—मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए अन्य उपाय सुझाये जाते हैं जो निम्नलिखित हैं :

(i) **उत्पादन में वृद्धि** (Increase in Production)—इसके लिए औद्योगिक व कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाये। यह वैज्ञानिक उपकरणों, आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति, मशीनों की व्यवस्था तथा कुशल प्रबन्ध एवं संचालन से सम्भव है। सरकार स्वयं उद्योग खोलकर उत्पादन बढ़ा सकती है।

(ii) **लाभ वितरण पर प्रतिबन्ध** (Restriction on Profit Distribution)—सरकार लाभ वितरण पर प्रतिबन्ध लगाकर हिस्सेदारों के लाभ को उपभोग पर व्यय करने से रोक सकती है। इससे उस सीमा तक मुद्रा-प्रसार पर नियन्त्रण सम्भव होगा।

(iii) **सट्टेबाजी पर प्रतिबन्ध** (Restriction on Speculation)—कुछ सट्टेबाज भावी सौदों से ऊँचे मूल्यों का मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न कर देते हैं जिससे मूल्यों का स्तर अनायास ही बढ़ जाता है। अतः इस पर नियन्त्रण भी सहायक सिद्ध होता है।

(iv) **मूल्य नियन्त्रण व राशनिंग** (Price Control and Rationing)—सरकार अपनी आर्थिक नीति के अन्तर्गत—(अ) वस्तुओं के अधिकतम मूल्य निर्धारित कर विक्रेताओं को बेचने को बाध्य कर सकती है। (ब) सरकार राशनिंग की नीति से आवश्यक वस्तुओं में मूल्य वृद्धि को रोकने में समर्थ हो सकती है। (स) मजदूरी की अधिकतम दर या Wages Freeze की नीति सहायक सिद्ध होगी। (द) इसी प्रकार आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की समूची व्यवस्था सरकार अपने हाथ में ले सकती है; जैसे—खाद्यान्नों का थोक व्यापार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया।

(v) **आयात प्रोत्साहन** (Export Promotion)—वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि के लिए सरकार आवश्यक आयातों को प्रोत्साहन दे सकती है तथा निर्यातों पर प्रतिबन्ध लगा सकती है। इससे मुद्रा-प्रसार का प्रभाव रोका जा सकता है।

(vi) **मजदूरी नीति** (Wages Policy)—मजदूरी की दरों में वृद्धि द्वारा वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण कीमतें बढ़ती हैं। कीमतें बढ़ने के कारण फिर मजदूरी बढ़ती है और यह क्रम चलता रहता है। यदि मजदूरी की दरों को स्थिर रखा जाये अथवा मजदूरी में वृद्धि का सम्बन्ध उसकी उत्पादकता से हो तो स्फीति को रोका जा सकता है।

(vii) **बेरोजगारी और कीमत स्थिरता** (Unemployment and Price Stability)—**फिलिप्स वक्र** (Phillips Curve)—पूर्ति के विश्लेषण के अध्ययन में रुचि रखने वाले अर्थशास्त्रियों ने विगत वर्षों में अपना ध्यान मजदूरी वृद्धि दर एवं बेरोजगारी के मध्य सम्बन्ध के अध्ययन पर केन्द्रित किया है। **प्रो. ए. डब्ल्यू. फिलिप्स** ने 1916 और 1957 के बीच ब्रिटेन में मजदूरी-दरों और बेरोजगारी के बीच बने रहने वाले सम्बन्ध के बारे में जो

Scanned with CamScanner

अनुसन्धान किया है, उससे इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि **बेरोजगारी का स्तर बढ़ाकर कीमतों की वृद्धि-दर में कमी लायी जा सकती है।** कारण यह है कि स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था की मजदूरी की लागत एवं कीमत-स्तर में बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अतः यह मानते हुए कि मजदूरी-दर के अनुरूप ही कीमतों में वृद्धि होती है, **फिलिप्स वक्र यह प्रदर्शित करता है कि बेरोजगारी के विभिन्न स्तरों पर कीमतों में सम्भावित परिवर्तन कितना होगा?** यदि हम स्फीति की दर को कम करना चाहते हैं तो हमें बेरोजगारी के अधिक स्तर के लिए तैयार रहना चाहिए। चित्र में PP फिलिप्स वक्र है जो बायीं ओर से दायीं ओर नीचे की ओर ढालू है। नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र यह दर्शाता है कि **मजदूरी वृद्धि स्फीति को बेकारी का स्तर बढ़ाकर समाप्त किया जा सकता है।**

यह उल्लेखनीय है कि **केवल वही मजदूरी वृद्धि-दर स्फीति उत्पन्न करती है जो श्रम की उत्पादकता में वृद्धि का परिणाम नहीं होती। चित्र 5.3 में WW समतल रेखा श्रम की उत्पादकता में प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित करती है अतः मजदूरी दर में OW प्रतिशत तक मजदूरी वृद्धि स्फीति उत्पन्न नहीं होती।**

प्रो. सैम्युलसन तथा **प्रो. सोलो** ने फिलिप्स वक्र को अमेरिका में लागू किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि कीमतों में स्थिरता रखने के लिए बेरोजगारी की दर $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत आवश्यक है, जबकि श्रम उत्पादकता की दर में $2\frac{1}{2}$ की वृद्धि होती है।

Scanned with CamScanner